भाजपा

सबका साथ
सबका विकास

केन्द्रीय चुनाव प्रबन्धन, कार्यक्रम एवं लॉजिस्टिक कमेटी द्वारा प्रकाशित

एक भारत
श्रेष्ठ भारत

भाजपा

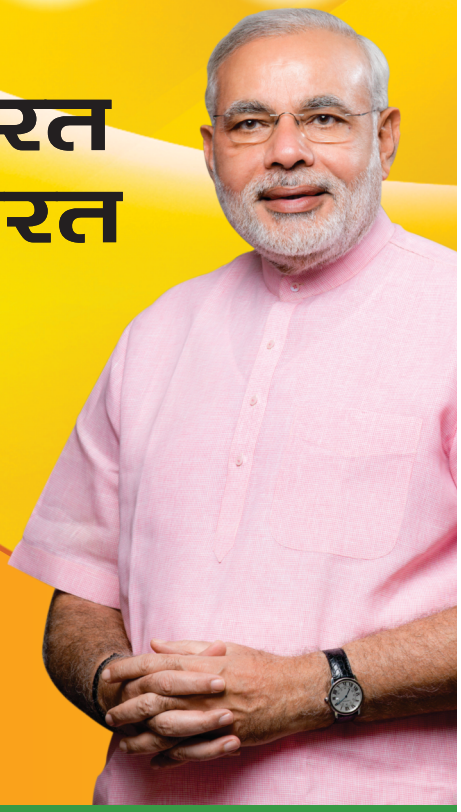

भाजपा चुनाव घोषणा पत्र 2014 (संक्षिप्त संस्करण)

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

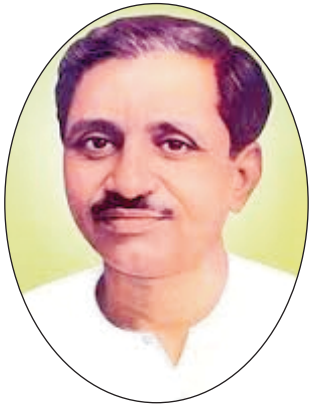

पं. दीनदयाल उपध्याय

भाजपा

"मैं तीन वादे करना चाहता हूँ, पहला यह कि व्यक्तिगत रूप में देश की जनता जो मुझे दायित्व देगी मैं उसे पूरा करने में कभी भी कोई कमी नहीं रंखूगा। दूसरा, मैं अपने लिये कभी कुछ नहीं करूंगा और तीसरी बात, मैं बद–इरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा। ये विश्वास दिलाता हूँ।"

– श्री नरेन्द्र मोदी

अनुक्रम

आसन्न चुनौतियाँ 02
महँगाई 02
रोजगार और उद्यमिता 03
भ्रष्टाचार 04
काला धन 04
निर्णय और नीतियों में अपंगता 04
कमजोर वितरण 05
विश्वसनीयता का संकट 05
कार्ययोजना की मजबूती 05
टीम इंडिया 05
केंद्र–राज्य संबंध 05
राष्ट्र का एकीकरण – इसकी व्यापकता और अभिव्यक्तियाँ 06
वकेंद्रीकरण और जनभागीदारी 08
प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र से भागीदारीयुक्त लोकतंत्र 08
व्यवस्था सुधार 08
सुशासन : पारदर्शी, प्रभावशाली, संलग्नकारी और प्रोत्साहनकारी सबसे पहले भारत 08
खुली सरकार और जवाबदेह प्रशासन 09
ई गवर्नेंस, आसान, सक्षम और प्रभावी 10
संस्थागत सुधार–प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस और निर्वाचन 11
प्रशासनिक 11
न्यायिक 11
पुलिस 12
निर्वाचन 13
अधिक व्यापक मंच 13
गरीब और अधिकारहीन – दरार को भरना 13
खाद्य सुरक्षा 14
एस.सी, एसटी और इसके गरीब तबके को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण 14
अल्पसंख्यक : समान अवसर 15
नव मध्य वर्ग–हासिल कर सकेंगे हसरतें 16
ग्रामीण क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता 16
शहरी क्षेत्र – उच्च वृद्धि केन्द्र 17
आगे की छलांग 17
सामाजिक सुरक्षा– एक फिक्रमंद सरकार; संवेदनशील समाज 17
बच्चे–राष्ट्र का भविष्य 17
वरिष्ठ नागरिक 18
शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति 18
युवा वर्ग– न रुकने वाला भारत 19
खेल संवर्धन 19
महिलाएं–राष्ट्र निर्माता 19
शिक्षा– पढ़ो और आगे बढ़ो 21
स्कूली शिक्षा 21
उच्च एवं पेशेवर शिक्षा 22
रोजगारपरक प्रशिक्षण 22
हुनर–उत्पादकता एवं रोजगारपरकता पर जोर 22
स्वास्थ्य सेवाएं–पहुंच बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, लागत को कम करना 23
आर्थिक पुनरुत्थान 25
एनपीए 25
कराधान– कर प्रणाली 25
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26
कृषि– उत्पादकता, विज्ञान और उसका पारितोषक 26
उद्योग– आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और देखभाल करने वाला 27
विनिर्माण 28
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) 28
सहकारी क्षेत्र 29
हस्तशिल्प 29
कारीगर 29
सेवाएं–गुणवत्ता व कुशलता पर आधारित 29
व्यवसाय व व्यापार 29
पर्यटन–असीम संभावनायें 30
श्रम बल – हमारी वृद्धि का स्तंभ 30
आवास– अब एक सपना नहीं 31
भौतिक आधारभूत ढांचा–सर्वोत्तम से भी बेहतर 31
भविष्य का आधारभूत ढांचा 32
परिवहन 32
रेलवे 32
पानी– इसे हर घर को, हर खेत को और कारखानों को उपलब्ध करना होगा 33
ऊर्जा : ज्यादा बनाओ, सावधानी से उपयोग करो, बर्बाद बिल्कुल न करो 33
विज्ञान एवं तकनीक : भारत नवाचार करता है तथा भारत नेतृत्व करता है 34
पेड़ पौधे, जीव जंतु और पर्यावरण – अपने भविष्य को सुरक्षित करना 36
प्राकृतिक तथा राष्ट्रीय संसाधन – आवश्यकता अनुसार उपयोग, जहां आवश्यक हो वहां संरक्षण 37
भारतीयों की सुरक्षा– आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध बिलकुल सहन नहीं होगा 37
आंतरिक सुरक्षा : भाजपा 38
बाह्य सुरक्षा : भाजपा 38
रक्षा उत्पादन 39
स्वतंत्र सामरिक नाभिकीय कार्यक्रम 39
विदेश संबंध–राष्ट्र प्रथम – वैश्विक बंधुता 40
सांस्कृतिक विरासत 41
समान नागरिक संहिता 42

भाजपा चुनाव घोषणा पत्र 2014
(संक्षिप्त संस्करण)

आज भारत को दुर्लभ क्षमता और डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी तथा डिमांड के अवसर का वरदान मिला हुआ है। अगर हम इन्हें समेकित करने और इस्तेमाल करने में सक्षम हुए, तो हम उन ऊँचाइयों को हासिल कर सकते हैं, जिनका भारत पात्र है। खराब हालत का सबसे बड़ा कारण उनके बुरे इरादे रहे हैं जिन्होंने साठ सालों तक देश पर राज किया है। और, ऐसे में ही हम अंतर दिखाएँगे। भाजपा के लिए नीतियों और क्रियान्वयनों का लक्ष्य होगा : **एक भारत, श्रेष्ठ भारत!** रास्ता होगा : **सबका साथ, सबका विकास।** राष्ट्र और इसकी जनता से यह हमारी प्रतिबद्धता है।

डॉ (प्रोफेसर) मुरली मनोहर जोशी
अध्यक्ष
चुनाव घोषणापत्र समिति – 2014

आसन्न चुनौतियाँ

यूपीए–1 और 2 के शासन वाले एक दशक को एक ही पंक्ति में ठीक से व्यक्त किया जा सकता है, 'गिरावट का दशक', जिसमें भारत में हर प्रकार की समस्याओं से निपटने में गिरावट ही आई है–फिर चाहे वह शासन हो, आर्थिक स्थिति हो, राजनयिक अपमान हो, विदेश नीति की असफलता हो, सीमापार घुसपैठ हो, भ्रष्टाचार और घोटाले हों या महिलाओं के साथ होने वाले अपराध हों। सरकार और संवैधानिक इकाइयों का भारी दुरुपयोग और पूर्ण अवमानना हुई है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी काफी पतन हुआ है। सरकार प्रतिदिन दुविधा में ही पड़ी रही जिसके कारण देश पर निराशा और विनाश के बादल मँडराते रहे, जबकि एनडीए के शासनकाल में भारत 'उभरती हुई महाशक्ति' कहलाने लगा था। 2004 में एनडीए के सत्ता छोड़ने के समय विकास दर दो अंकों के करीब थी। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार उसको भी कायम नहीं रख पाई और सरकार का प्रबंधन इतने खराब तरीके से उसने किया कि विकास दर गिरकर 4.8 प्रतिशत तक आ गई और देश गहरे संकट में फंस गया। हमने एक सुंदर अवसर गँवा दिया और देश को बीस साल पीछे धकेल दिया। लाखों–करोड़ों महिला–पुरुषों को बेरोजगार कर दिया।

देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण और तात्कालिक चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया। इनका असर तात्कालिक स्थिति पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इससे देश की दीर्घकालीन क्षमताओं पर भी बुरा असर पड़ा। लोग कुंठित महसूस कर रहे हैं और उनका विश्वास व्यवस्था से हट गया है। चीजें बदलनी ही होंगी, और अब वे जरूर बदलेंगी। भाजपा इन सारे मसलों का हल प्राथमिकता के आधार पर निकालने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाएगी।

महँगाई

खाने–पीने के सामान के बढ़ते दामों ने घरों का बजट बिगाड़ दिया है और कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की देखरेख में कुल मिलाकर महँगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। यहाँ तक कि लाखों–करोड़ों लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हालाँकि, कांग्रेस नीत

यूपीए सरकार संवेदनहीन बनी रही और लोगों की दशा की उसने कोई परवाह नहीं की वह तो अल्पकालिक और दिशाहीन कदमों में खुद को उलझाए रही। श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने खाद्य महंगाई पर 2011 में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। दुर्भाग्य से उस रिपोर्ट पर कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने कोई काम नहीं किया। तात्कालिक बीजेपी नीत एनडीए सरकार के समय महंगाई के स्थिर रहने का रिकॉर्ड हमारे उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरों के विद्वेषपूर्ण कुचक्र को तोड़ने के संकल्प को दर्शाता है। हमारा तात्कालिक कार्य अनेक कदम उठाकर महंगाई पर लगाम लगाने का होगा, जैसे कि :

- जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े उपाय करना और **विशेष अदालतें** स्थापित करना।
- **दाम स्थिरीकरण कोष** की स्थापना करना।
- भारतीय खाद्य निगम के संचालन को वृहद क्षमता के साथ खरीदारी, भंडारण, और वितरण के लिए खोलना।
- विशेषकर किसानों के लिए–उत्पादन, कीमतों, आयात, भंडार और समग्र उपलब्धता के बारे में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वास्तविक समय को घटाना।
- एकल **'राष्ट्रीय कृषि बाजार'** का विकास करना।

रोजगार और उद्यमिता

देश कांग्रेस नीत यूपीए सरकार द्वारा 10 सालों से **रोजगारविहीन विकास** में घसीटा जा रहा है। व्यापक आर्थिक पुनरुत्थान के तहत, भाजपा रोजगार सृजन और उद्यमिता के अवसरों को उच्च प्राथमिकता का वादा करती है। इसके तहत हम :

- **श्रम आधारित निर्माण** (कपड़ा, जूता, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान एसेंबलिंग आदि) और **पर्यटन** का रणनीतिक आधार पर विकास करेंगे।
- कृषि और संबंधित उद्योगों और खुदरा के परंपरागत रोजगारों को आधुनिकीकरण के साथ–साथ मजबूत साख और बाजार संपर्कों के जरिए मजबूत करेंगे।
- अधोसंरचना और **आवास के सुधार** के जरिए उपलब्ध कराए गए अवसरों का इस्तेमाल करेंगे और इनकी रोजगार सृजन की क्षमता का इस्तेमाल करेंगे।
- अपने युवाओं को उद्यमिता तथा ऋण की सुविधा के जरिए स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित और सशक्त करेंगे।
- सेवा भाव से बहु–कौशल कार्यक्रम शुरू करके रोजगार की समस्या हल करेंगे। इसमें ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन और उद्यमिता पर जोर दिया जाएगा।
- अपने रोजगार कार्यालयों को रोजगार केन्द्रों के रूप में बदलेंगे।

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार कमजोर शासन का नतीजा होता है। इसके साथ ही यह सत्ता में बैठे लोगों की बुरी नीयत को भी प्रकट करता है। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार में फैला सारा व्यापक भ्रष्टाचार **'राष्ट्रीय संकट'** बन गया है।

हम ऐसा तंत्र स्थापित करेंगे जो भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही समाप्त कर देगा। हम इसके लिए निम्न उपाय करेंगे :

- जन जागरूकता
- प्रौद्योगिकी आधारित ई–गवर्नेंस।
- प्रणाली आधारित, नीति प्रेरित शासन ।
- कर प्रणाली को तर्कसंगत और सरलीकृत किया जाएगा।
- सभी स्तरों पर प्रक्रियाओं और तरीकों का सरलीकरण।

काला धन

भ्रष्टाचार की गजुांइश न्यनूतम करके, हम काला धन पैदा न होने को सुनिश्चित करेंगें भाजपा विदेशी बैंकों और समुद्र पार के खातों में जमा काले धन का पता लगाने और उसे वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस काम के लिए और मौजूदा कानूनों में बदलाव करने या नए कानून बनाने के लिए हम एक कार्यबल स्थापित करेगें। कालेधन को वापस भारत लाने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। हम विदेशी सरकारों से भी कालेधन से जुड़ी जानकारियाँ हासिल करने के लिए व्यापक पहल करगें।

निर्णय और नीतियों में अपंगता

देश एक दशक तक कुप्रशासन और घोटालों से पीड़ित रहा है, साथ में निर्णयों और नीतियों में अपंगता की स्थिति भी रही है। इस प्रकार वृद्धि और विकास को कष्टदायी स्थिति में रोकने से 'सरकारी घाटे' की स्थिति बन गई है। यह स्थिति बदली जाएगी और सरकार का इंजन दोबारा मजबूत इच्छाशक्ति और जनहित के लिए प्रतिबद्धता के साथ शुरू किया जाएगा। हम नौकरशाही को सही निर्णय लेने और अपनी ताकत का इस्तेमाल आधुनिक भारत के निर्माण में करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

कमजोर वितरण

हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हर जगह बाधाएँ ही दिखती हैं। हम रोजाना इसे अनुभव करते हैं–सरकारी कार्यालयों में जनता के छोटे से छोटे काम में अड़चनें हैं, हम अधूरे काम और काम पूरा न हो पाने की संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इससे कामकाज की गति कम होती है और परिणामस्वरूप समय, धन और ऊर्जा की बरबादी होती है। सही काम करने के लिए सही दिशा भी होनी जरूरी है, लेकिन उसका अभाव है। इसे प्राथमिकता के आधार पर हासिल करना होगा। हम जो भी करते हैं, उसके लिए हमें पूरी श्रंखला को ध्यान में रखना होगा। हम इसको ध्यान में रखते हुए निम्न उपाय करेंगे :

- सभी क्षेत्रों, गतिविधियों और सेवाओं में बाधाओं और अधूरेपन को हटाएँगे।
- सही परिणामों के लिए उचित नियोजन और क्रियान्वयन पर जोर देंगे।
- भविष्यगामी सोच के साथ मात्रा और गति पर जोर देंगे।
- आज और कल के लिए संस्थाओं का निर्माण करेंगे।

विश्वसनीयता का संकट

भारत के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार की विश्वसनीयता और भरोसे की बहाली की है। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने विश्वसीयता पूरी तरह से खो दी है। इसकी नीयत, ईमानदारी और कामकाज, सब सवालों के दायरे में हैं। कांग्रेस पार्टी ने न केवल सरकार की, बल्कि भारत की भी मर्यादा गिराई है। यही कारण है कि रुपए के अवमूल्यन और बाकी देशों के हमारे ऊपर हावी होने देने जैसी ताजा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं। भाजपा सरकार के भरोसे और विश्वसनीयता की बहाली के लिए काम करेगी। हम प्रणाली में जिम्मेदारी और जवाबदेही की श्रंखला भी सुनिश्चित करेंगे।

कार्ययोजना की मजबूती

टीम इंडिया

केंद्र–राज्य संबंध

हर राज्य की स्वाभाविक परेशानियाँ व्यापक रूप से निपटाई जानी चाहिए।

- हम केंद्र–राज्य संबंधों को सलाह–मशविरा करके सहज बनाएँगे और केंद्र–राज्यों के सद्भावपूर्ण संबंधों की दिशा में प्रयास करेंगे।
- हमारी सरकार राज्यों के तीव्र विकास में मददगार बनेगी और अनुकूल रहेगी। हम राष्ट्रीय विकास का एक मॉडल तैयार करेंगे, जो कि **राज्यों द्वारा संचालित** होगा।
- टीम इंडिया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में बैठी टीम ही नहीं होगी, बल्कि मुख्यमंत्रियों और अन्य अधिकारियों को भी इसमें समान भागीदार बनाया जाएगा।

- राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित की जाएगी।
- समान समस्याओं और सरोकारों के साथ 'राज्य क्षेत्रीय परिषदों' का गठन किया जाएगा।
- हम सुरक्षा सबंधी मुद्दों, अतंर–राज्यीय विवादों के साथ–साथ अतंर–क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं को हटाने तथा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों से सहयागे को बढ़ावा देगें ।
- केंद्र शासित प्रदेशों की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जनजातियों के कल्याण और उनके अधिकारों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और अधोसंरचना तथा तटीय क्षेत्र विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी।
- हम अपने द्वीपीय क्षेत्रों के संरक्षण और एकीकृत विकास की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।
- राष्ट्रीय विकास परिषद' और 'अतंर–राज्यीय परिषद जैसे मृतप्राय मंचों को पुनर्जीवित किया जाएगा ।
- विदेश व्यापार और वाणिज्य के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकारों को शामिल किया जाएगा।

राष्ट्र का एकीकरण – इसकी व्यापकता और अभिव्यक्तियाँ

हमें अपनी सोच और कार्यों में राष्ट्रीय को सबसे आगे रखना होगा। देश की अखडंता को किसी भी तरह से नुकसान पहुचाँने वाला कोई भी कार्य समाज के किसी भी वर्ग या देश के किसी भी क्षेत्र के हित में नहीं हो सकता।

- वर्तमान में, हमें विकास के पैमाने पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच भारी क्षेत्रीय विषमता देखने को मिलती हैं।
- हम देश के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से के समकक्ष लाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।
- सरकार इन राज्यों के तीव्र विकास में मददगार और अनुकूल भूमिका निभाएगी। **क्षेत्रीय आकांक्षाओं, मजबूती और संभावनाओं की योजना बनाएगी,** देश के विभिन्न हिस्सों–पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों– के विकास के लिए उचित रणनीतियाँ बनाएगी।
- **क्षेत्रीय आकांक्षाएँ** : भाजपा सदैव छोटे राज्यों के जरिए वृहद विकेंद्रीकरण के पक्ष में रही हैं।

पूर्वोत्तर : संसाधनों में समृद्ध पूर्वोत्तर के राज्य कमजोर शासन, व्यवस्थागत भ्रष्टाचार और जन सेवाओं के कमजोर वितरण के कारण विकास में पीछे छूट रहे हैं। एनडीए सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय का गठन करके पूर्वोत्तर के विकास के मुद्दे के हल के लिए ठोस कदम उठाए थे। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए इस मंत्रालय को व्यापक घोषणापत्र और रद्द न होने वाले कोष के जरिए सशक्त बनाएंगे। भाजपा इस दिशा में निम्न कदम उठाएगी :

- क्षेत्र के अंदर और देश के बाकी हिस्सों से संपर्क मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ व्यापक अधोसंरचना पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- असम में बाढ़ नियंत्रण और नदी जल प्रबंधन के मुद्दे को हल किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर में घुसपैठ और अवैध प्रवासियों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।
- भारत–बांग्लादेश और भारत–म्यांमार सीमा पर बाकी बचे बाड़ लगाने के काम को पूरा किया जाएगा, और सीमा सुरक्षा को चाक–चौबंद किया जाएगा।
- देश भर में पढने वाले पूर्वोत्तर के छात्र–छात्राओं की सुरक्षा के उपाय किए जाएगें। इनके तहत विभिन्न शैक्षणिक केंद्रों में पूर्वोत्तर के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएगें।
- उपद्रवी तत्वों से कड़ाई से निपटा जाएगा।

जम्मू और कश्मीर : जम्मू और कश्मीर भारत संघ का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत की भौगोलिक एकता अखंड है। भारत इस राज्य के तीनों हिस्सों–जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, के समान और तीव्र विकास के एजेंडे को लागू करेगी।

- कश्मीरी पंडितों की अपने पूर्वजों की भूमि में ससम्मान, सुरक्षित और सुनिश्चित आजीविका के साथ वापसी सुनिश्चित करना बीजेपी के एजेंडे में उच्च स्थान पर रहेगा।

- पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के व अन्य शरणार्थियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं और माँगों को हल किया जाएगा।
- भाजपा धारा 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराती है और इस पर सभी पक्षों से चर्चा करेगी तथा इस धारा को हटाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

आंध्र और तेलंगाना : भाजपा तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद आंध्र के साथ पूरा न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र और तेलंगाना के विकास और शासन से संबंधित सारे मुद्दे हल किए जाएँगे।

विकेंद्रीकरण और जनभागीदारी

प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र से भागीदारीयुक्त लोकतंत्र

भाजपा राज्यों को अधिकार देने के जरिए वृहद विकेंद्रीकरण के पक्ष में खड़ी है।

- **जनभागीदारी** : हमारी विकास प्रक्रिया जन भागीदारी के जनांदोलन की होगी।
- **जन संलग्नता** : अग्र सक्रिय, जनोन्मुखी सुशासन के जरिए हम सुनिश्चित करेंगे कि सरकार स्वयं ही लोगों तक पहुँचे।
- पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल का विकास आगे **पीपुल–पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप** (पीपीपपीपी) मॉडल के रूप में करेंगे।
- भाजपा स्थानीय स्तर पर स्वशासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम पंचायती राज संस्थाओं को तीन **एफ–फंक्शन, फंक्शनरीज और फंड के** जरिए सशक्त करेंगे।
- अच्छा काम करने वाली पंचायतों को अतिरिक्त विकास अनुदानों जैसे पुरस्कार दिए जाएंगे।
- **ग्राम सभा** संस्था को उनके कार्यों और विकास प्रक्रियाओं की पहलों के संदर्भ में मजबूत किया जाएगा।

व्यवस्था सुधार

सुशासन : पारदर्शी, प्रभावशाली, संलग्नकारी और प्रोत्साहनकारी

सबसे पहले भारत

भाजपा का मानना है कि एक देश, एक जनता और एक राष्ट्र के रूप में भारत एक है। भारत अपने सारे लोगों से मिलकर बना है। जाति, नस्ल, धर्म और लिंग के किसी भी भेद से एकदम परे। इसमें हमारी संस्कृति भी है जिसे सहिष्णुता और सह–अस्तित्व के द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसमें अनेकता भी है, जिसे सहेजते हुए हम अब तक एक बने हुए हैं। इसमें हमारी एक–एक इंच भूमि शामिल है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या

सीमा की हो। इसमें सारे प्राकृतिक संसाधन, हमारी मानसिक और भौतिक ऊर्जा भी शामिल है। इसमें अतीत और वर्तमान में बनी सारी संस्थाएँ शामिल हैं।
सबसे पहले भारत का सरल अर्थ उन सारे तत्वों का पोषण और संरक्षण है जिनसे भारत बना है।
भाजपा के लिए :

- किसी भी सरकार का एकमात्र दर्शन और धर्म **सबसे पहले भारत** होना चाहिए।
- सरकार का एकमात्र धर्मग्रंथ **भारत का संविधान** होना चाहिए।
- सरकार की एकमात्र शक्ति **जनशक्ति** होनी चाहिए।
- सरकार की एकमात्र प्रार्थना उसकी **जनता की भलाई** होनी चाहिए।
- सरकार का एकमात्र रास्ता **'सबका साथ, सबका विकास'** होना चाहिए।

खुली सरकार और जवाबदेह प्रशासन

प्रशासनिक सुधार भाजपा के लिए प्राथमिकता होंगे। इसके लिए हम उनका क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत एक उचित संस्था के जरिए करने का प्रस्ताव करते हैं। इसका उद्देश्य सरकार की निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। हम एक प्रभावी लोकपाल संस्था गठित करेंगे। हर स्तर के भ्रष्टाचार से कड़ाई और तीव्रता से निपटा जाएगा। इस दिशा में निम्न विशिष्ट कदम उठाए जाएंगे :

- सरकारी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा जाएगा ।
- कामकाज की समीक्षा, सामाजिक और पर्यावरणीय अंकेक्षण सारी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य होगा।
- सरकार में उद्योग, शिक्षाजगत और समाज के लोगों को शामिल किया जाएगा और उनकी सेवाएँ ली जाएँगी।
- अप्रचलित कानूनों, नियमों, प्रशासनिक संरचनाओं, तरीकों को हटाकर उन्हें पुर्नपरिभाषित किया जाएगा और उन्हें उद्देश्यपूर्ण बनाया जाएगा।
- हम सरकारी कर्मचारियों के अंदर **'कर्तव्य भावना'** पैदा करेंगे क्योंकि लोगों का जीवन और उत्पादकता सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता पर निर्भर करती है।

कुल मिलाकर, हमारे शासन मॉडल का हॉल मार्क निम्न बिंदु होंगे :

- **जन केंद्रित**
- **नीति प्रेरित**
- **समयबद्ध वितरण**
- **न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन**

ई गवर्नेंस, आसान, सक्षम और प्रभावी

भाजपा का विश्वास है कि समानता और प्रभावोत्पादन के लिए सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। यह भाजपा के लिए उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है क्योंकि आईटी सामान्य लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। भाजपा सुशासन के बारे में जानती है और ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस की रीढ़ होगी। भाजपा का उद्देश्य है एक डिजिटल इंडिया का निर्माण जिससे हर घर और हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से डिजिटल तरीके से सशक्त बनाया जा सके।

- ग्रामीण और अर्धशहरी (semiurban) इलाकों में आईटी आधारित नौकरियां सृजित की जायेंगी।
- छात्रों के लिए तकनीक से जुड़े उत्पाद बनाये जायेंगे जो उनकी आर्थिक पहुंच के अनुकूल हों।
- सभी संस्थानों और स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से सूचना तकनीक योग्य बनाया जायेगा। डिजिटल शिक्षा और प्रशिक्षण के उपयोग का विस्तार किया जायेगा।
- नेशनल रूरल इंटरनेट और टेक्नॉलाजी मिशन के तहत एक मिशन चलाया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए टेलिमेडिसिन और चल चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा दिया जायेगा। सही समय पर जानकारी के लिए कृषि क्षेत्र में आईटी का उपयोग किया जायगा। स्व–स्वास्थ्य समूह, खुदरा क्षेत्र और लघु क्षेत्र और ग्रामीण उद्योगपतियों को बढ़ावा देने में भी इनका उपयोग होगा।
- एक राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना शुरु की जायेगी जो केन्द्र से लेकर पंचायत तक सभी सरकारी कार्यालयों को कवर करेगी। गुजरात में लागू की गई **''ई–ग्राम विश्वग्राम स्कीम''** पूरे देश में लागू की जायेगी।
- ई–भाषा को बढ़ावा देंगे–राष्ट्रीय मिशन के लिए भारतीय भाषाओं को आईटी में प्रोत्साहित करेंगे।
- एस.सी / एसटी., ओबीसी और दूसरे कमजोर वर्गों के विकास के लिए, कल्याण के लिए आईटी से जुड़ा विकास करेंगे।
- भारत की अमूल्य संस्कृति, कला की विरासत को सुसंस्कमरण देने में आई टी का इस्तेमाल करेंगे इसमें सभी संग्रहालय और पुरालेख का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा।
- खुला स्रोत और खुले मानक साफ्टवेयर को वरीयता दी जायेगी।
- सरकार के हर कार्य की आधार सामग्री तैयार होगी। जिससे भ्रष्टाचार और काम की देरी में कमी आयेगी।
- तीव्रगति का डिजिटल हाइवे तैयार होगा जिससे देश को एकता में पिरोया जा सके।
- तकनीक का इस्तेमाल संचारण और वितरण की हानियों को कम करने में किया जाएगा।

- वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए मोबाइल और ई–बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

संस्थागत सुधार–प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस और निर्वाचन

प्रशासनिक

हमारा प्रसाशनिक ढांचा व्यक्ति केन्द्रित, जवाबदेह और परिणाम देने वाला होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- प्रशासन और इसके सदस्य वास्तव में उनको दिए काम के प्रति **उत्तरदायी** होंगे जिससे कि लोग वृहद विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें।
- बेहतर प्रदर्शन करने वालों को **सम्मानित** (पुरस्कृत) किया जाएगा, जो अच्छा नहीं कर पाएंगे उन्हें अवसर और प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे बेहतर कर सकें।
- मंत्रालयों का तार्किकरण और विलय किया जायगा। विभाग और सरकार की दूसरी शाखाओं को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका फोकस परिणाम पर हो।
- युवाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर फेलोशिप और इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरु किए जायेंगे जिससे सरकार को उनकी सेवाएं विशेष रूप से मिल सकें।

न्यायिक

सबके लिए न्याय सुनिश्चित कराने के लिए बीजेपी कटिबद्ध है। न्याय वह जो सही समय पर और सहज मिले।

- न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए प्राथमिकता के आधार पर जजों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्त पद भरे जाएंगे, नये कोर्ट खुलेगें, एक एकसी प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों का निपटारा हो।
- मिशन की तरह एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिससे न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरा जाए। अदालतों की संख्या और निचली अदालतों में जजों की संख्या दोगुनी की जाएगी।
- उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा।
- कोर्ट की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए एक फंड होगा।

- अलग से विशेष अदालतों का गठन किया जायेगा जिन में वाणिज्य सम्बन्धी कानून के मामलों का द्रुतगति से निपटारा किया जायेगा।
- अलग तरीके की कोर्ट बनाई जाएगी जिसमें विशेष वाणिज्यिक कानूनों की जरूरत होगी।
- आपराधिक न्यायप्रणाली में सुधार किया जाएगा।
- न्यायिक प्रणाली के सभी स्तरों पर द्रुतगति अदालतों का गठन किया जाएगा।
- लोक अदालत और न्यायाधिकरण जैसी प्रणाली भी विकसित की जाएगी।
- नैशनल लिटिगेशन पॉलिसी बनाई जाएगी।
- अगले 5 साल में सरकार ने जो याचिका दायर की है उन मामलों की संख्या समीक्षा बैठकों के बाद तार्किक तरीके से कम की जायेगी।
- समय–समय पर कानूनों की समीक्षा होगी और पुराने अप्रचलित कानूनों को हटा दिया जाएगा।
- आईपीआर केसों को निपटाने के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी।
- विवादों के वैकल्पिक निपटारे का तंत्र विकसित करने के लिए विशेष रूप से प्रयास किया जाएगा जैसे **लोक अदालत, न्यायाधिकरण और समझौता केन्द्र**।
- वकीलों के सशक्तिकरण के लिए एक विशेषीकृत राष्ट्रीय **ई–पुस्तकालय** बनाया जायेगा।
- न्यायपालिका में लिंग भेद कम करने के लिए वकालत व न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
- कानून में सहायता देने वाली **विशेषीकृत विश्वविद्यालयों** की स्थापना की जाएगी जो फोरेसिंक, पचं फैसला (अर्बिट्रेशन) बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) और अतंराष्ट्रीय कानूनों में विशेषता हासिल कराएगी।
- भारत को पंचफैसला और विधिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग का केन्द्र बनाया जाएगा।
- ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें कानूनी जानकारी सबको मुफ्त उपलब्ध हो।
- कानून की जानकारी देने के लिए जगरुकता अभियान चलाए जाएंगे और इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा।

पुलिस

हम राज्यों के साथ मिलकर उन्हें अधिकार देकर सशक्त बनाएंगे, उन्हें आवश्यक स्वतंत्रता और संसाधन उपलबध कराएंगे।

- एक ऐसी विस्तृत रणनीति तैयार करेंगे जिससे भारतीय पुलिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो सके।

- पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी।
- पुलिस का **आधुनिकीकरण** किया जाएगा।
- सतत् प्रशिक्षण, विशेषकर कौशल विकास के जरिए जांच में विशेषीकृत दक्षता विकसित की जायेगी।
- तकनीक और बुनियादी सुविधाओं के साथ जेल व्यवस्था, कैदियों की व्यवस्था या जेल तत्रं का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- एक समान राष्ट्रीय मानक और क्रमाचार बनाने के क्षेत्र में काम किया जाएगा। पुलिस को प्रशिक्षित किया जाएगा, उसे ऐसी तकनीक दी जाएगी कि वह साइबर अपराध समेत तमाम अपराधों पर लगाम लगाने में सक्षम हो।
- पुलिस कर्मियों की **कार्य दशाओं को सुधारने** के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

निर्वाचन

भाजपा चुनाव सुधार करने के लिए कटिबद्ध है जिससे अपराधियों को राजनीति से बाहर किया जा सके भाजपा दूसरे दलों के साथ विचार विमर्श करके ऐसा तरीका बनाना चाहती है जिससे विधानसभा और लोक सभा के चुनाव साथ–साथ हों इससे सरकार और राजनैतिक दलों का खर्च कम होगा। इससे राज्य सरकार में थोड़ी स्थिरता आएगी। हम चुनाव में खर्च की सीमा में बदलाव लाना चाहते हैं।

अधिक व्यापक मंच

वह सरकार की जिम्मेदारी है कि हर भारतीय को अपनी क्षमता का अहसास हो और विकास की धारा समान रूप से बहे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सुनिश्चित करायेंगे कि

- प्रत्येक भारतीय **स्वास्थ्य और शैक्षिक** दृष्टि से मजबूत हो।
- **रोजगार** के अवसरों को बढ़ावा हमारे आर्थिक मॉडल का केन्द्र बिन्दु होगा।
- सभी के लिए **बुनियादी सुविधाएं,** घर बिजली, पानी, शौचालय व अन्य चीजें उपलब्ध कराएंगे।

गरीब और अधिकारहीन – दरार को भरना

हमारी सरकार गरीब, हासिए पर पड़े लोगों और पीछे रह गए लोगों की होगी।

हम अन्त्योदय की अवधारणा में विश्वास करते हैं– जिसमें गरीब को ऊपर उठाना है। अतिशय गरीबी और कुपोषण की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता से हल करना है। इसे हम मिशन के तरीके से लाएंगे।

- गरीबी दूर करने के प्रोग्राम और मजबूती से चलांएगे।

- देश के 100 अति पिछड़े जिलों की पहचान की जाएगी। एकीकृत विकास के ढाचें में लेकर इन्हें दूसरे जिलों के समकक्ष बनाया जाएगा।
- गांवों में कृषि व दूसरे कार्यों में लगे गरीब लोगों को कुछ अर्जित करने लायक बनाया जाएगा।
- सरकार के हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, सिविल सोसायटी, आकदमिक और वित्तीय संस्थान मिलकर गरीबी मिटाने का काम करेंगे।

खाद्य सुरक्षा

भाजपा का हमेशा से मानना रहा है कि सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भाजपा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि इन योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे और भोजन का अधिकार सिर्फ कागज पर बना एक कानून या राजनीतिक नारा न रह जाए। भाजपा राज्यों के साथ मिलकर सभी कानूनों और योजनाओं की समीक्षा करेगी ताकि खाद्य सुरक्षा के भ्रष्टाचार मुक्त प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। ये हमारी प्राथमिकता होगी :

भाजपा करेगी–

- सफल पीडीएस मॉडल की समीक्षा और वर्तमान में चल रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव जिससे आम आदमी को लाभ मिले।
- कुपोषण और भोजन की कमी की समस्या पर ध्यान देना।
- फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया के ढांचे में आमूल चूल बदलाव।

एस.सी, एसटी और इसके गरीब तबके को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण

भाजपा **सामाजिक समरसता** और **सामाजिक न्याय** के सिद्धातों का पालन करने के लिए कटिबद्ध है। पार्टी इसमें आ रही दूरी पर पुल बनाना चाहती है। यही सामाजिक न्याय आगे चलकर आर्थिक न्याय और राजनीतिक सशक्तिकरण दिलाता है। इनके नाम पर राजनीति करने की अपेक्षा हम सामाजिक दबे कुचले लोगों के सशक्तिकरण पर फोकस करेंगे। इसके लिए हम ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर का समान अवसर मिले। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता इन्हें सुरक्षा प्रदान करने की है, विशेषकर एससी/एसटी के लिए भेदभाव को देखते हुए।

- भाजपा हर स्तर पर छुआछूत और अश्पृश्यता खत्म करने के लिए कटिबद्ध है।
- भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि एससी/एसटी और ओबीसी के लिए जिस फंड की व्यवस्था की गई है उसका बेहतर तरीके से उपयोग हो।
- इनके घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलेपमेंट के लिए एक मिशन चलाया जाएगा। इस सोसाइटी के बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के शिक्षा स्वास्थ और दक्षता के बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आदिवासियों का विकास एक बड़ा मुद्दा होगा। गुजरात, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें आदिवासी कल्याण की योजनाएं सफलतापूर्वक चला रही हैं इनके मॉडल और योजनाओं को आदिवासियों के कल्याण और विकास में इस्तेमाल हो सकता है।
राष्ट्रीय स्तर पर वन बंधु कल्याण योजना शुरु की जाएगी जो आदिवासी कल्याण अथॉरिटी के तहत काम करेगी। इस स्कीम से इन बिंदुओं पर फोकस होगा।

- आदिवासियों के लिए एक शैक्षिक प्रणाली विकसित की जाएगी।
- घर, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
- आदिवासी इलाकों में बिजली मुहैया कराई जाएगी सभी मौसम में चलने लायक सड़कें होंगी।
- आदिवासियों के परंपरागत उत्पादों को प्रमोशन के लिए पर्यटन वाली जगहों और दूसरी जगहों पर आदिवासी बाजार (ट्राइबल हाट) खोले जाएंगे।
- आदिवासियों की संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने के लिए आदिवासी शोध एवं संस्कृति के राष्ट्रीय संख्या की स्थापना की जाएगी। (नेशनल सेंटर फॉर ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चर)
- आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए फंड में बड़ोत्तरी की जाएगी।

अल्पसंख्यक : समान अवसर

भाजपा का विश्वास है कि भारत विभिन्नता में एकता वाला देश है। भाजपा इस समृद्ध संस्कृति को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अल्पसंख्कों से जुड़े उन स्मारकों को भी, इसके साथ ही उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना चाहती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी अल्पसंख्सकों का एक बड़ा समूह विशेषकर मुस्लिम समुदाय लगातार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। आधुनिक भारत समान अवसर वाला होना चाहिए। भाजपा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत के विकास में सभी समुदाय की समान भागीदारी होनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि अगर कोई समुदाय पीछे छूट गया तो भारत प्रगति नहीं कर सकता। हम करेंगे–

- हम यह सुनिश्चित कराएंगे कि युवा, विशेषकर लड़कियों को शिक्षा मिले और बिना किसी भेदभाव के नौकरी मिले।

- अल्पसंख्यक शैक्षणिक व्यवस्था और संस्थानों को सशक्त एवं आधुनिक बनाया जायेगा।
- राष्ट्रीय **मदरसा आधुनिकीकरण** कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।
- उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उद्योग के क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- धार्मिक नेताओं से बातचीत करके **वक्फ बोर्ड** को और मजबूत किया जाएगा। ऐतिहासिक जगहों की संरक्षण और मेंटिनेंस रखरखाव किया जाएगा।
- **इटंरफेथ कंसल्टेटिव मकेनिज्म**–आतंरिक रूप से विश्वसनीय प्रणाली बनाई जाएगी जिससे आपसी विश्वास व भाईचारे का माहौल बना रहे, यह धार्मिक नेताओं की देखरेख में इसका काम होगा।

नव मध्य वर्ग–हासिल कर सकेंगे हसरतें

भारत एक विशाल मध्यवर्ग वाला देश है जिसमें योग्यता भी है और खरीदने की क्षमता भी। इसके अतिरिक्त एक नये वर्ग का उदय हो रहा है। वे लोग जो गरीबी से ऊपर उठे व अंश मध्य वर्ग में आए अब नव मध्यवर्ग में है, यह वर्ग बहुत तेजी से हासिल करना चाहता है। यह गरीबी से निकल चुका है इसकी हसरतें बढ़ गई हैं। सरकार इन सबका ख्याल रखते हुए ये उपलब्ध कराएगी –

- शैक्षिक छात्रवृत्ति और शैक्षिक सुविधाएं।
- स्वास्थय बीमा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं।
- मध्य आए इनकम वाले घर।
- प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली।

ग्रामीण क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता

कृषि, ग्रामीण विकास और गरीबी रेखा से निकालना हाथ के हाथ होगा। मुख्य लक्ष्य होगा ग्रामीण विकास का उसमें गांव की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना, रोड़, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वितरण प्रणाली, बिजली, ब्राडबैंड, नौकरी की उम्मीद, ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा और इसे बाजार से जोड़ना मुख्य होगा।

शहरी क्षेत्र – उच्च वृद्धि केन्द्र

- हम शहरीकरण को एक अवसर के रूप में देखते हैं न कि समस्या की तरह।
- शहरी क्षेत्र को और ऊपर उठाने के लिए परिवहन और हाउसिंग के क्षेत्र में और कदम उठाने होंगे।
- हम 100 नए शहर बसाने की शुरुआत करेंगे। नवीन तकनीक और बुनियादी सुविधाएं इस तरह की बनाई जाएंगी जिससे सतत विकास की धारणा मजबूत हो जिसमें चलते–चलते काम हो जाए और इसमें विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा।
- शहरी विकास एकीकृत परिस्थिति निकायी पर आधारित होगा जिसमें **जुड़वा शहर** और **सेटेलाइट टाउन** बनाए जा सकेंगे।
- **सफाई और स्वच्छता** हमेशा प्राथमिकता में होंगे, सक्षम कूड़ा निस्तारण और पानी प्रबंधन की व्यवस्था होगी। मॉडल टाउन–एकीकृत कूड़ा निस्तारण प्रणाली से पहचाने जाएंगे।
- **वाई–फाई** सुविधा सार्वजनिक स्थानों और व्यापारिक संस्थानों के पास उपलब्ध रहेगी।
- शहर की गरीबी दूर करना मूल मूल्य होगा।

आगे की छलांग

सामाजिक सुरक्षा– एक फिक्रमंद सरकार; संवेदनशील समाज

भारत हमेशा से ही एक परस्पर ख्याल रखने वाला समाज रहा है। बुजुर्गों कमजोरों और निस्सहायों की मदद करना हमारी संस्कृति में रहा है। सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाना होगा।

बच्चे–राष्ट्र का भविष्य

भाजपा बच्चों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों की अस्तित्व–रक्षा, विकास, भागीदारी एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा निम्न कदम उठाएगी–

- दुर्बल बच्चों और खास तौर पर अनुसुचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विस्थापितों, झुग्गीवासियों, फुटपाथ पर रहने वालों एवं विकलांगों जैसे कमजोर समुदायों के बच्चों पर विशेष जोर देगी।
- शिक्षा का अधिकार, खाद्य अधिनियम का अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
- बाल एवं किशोर श्रम (निवारण एवं विनियमन) कानून, 2012 तथा एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आईसीपीएस) की समीक्षा करेगी, संशोधन करेगी और सुदृढ़ बनाएगी।
- रक्ताल्पता के मसले का समाधान करने के लिए संकेन्द्रित प्रयास करेगी।

वरिष्ठ नागरिक

भाजपा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण विशेषकर उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मसलों से निपटने के लिए हम संगठित तरीके से कदम उठाएंगे।

- भाजपा उन्हें वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी। इसके लिए वह अतिरिक्त कर लाभागों एवं उच्च ब्याज दरों जैसे उपायों पर गौर करेगी।
- भाजपा वृद्धाश्रमों की स्थापना करने और उन्हें बेहतर बनाने में निवेश करेगी।
- भाजपा राष्ट्रीय हित में उनके अनुभव का उपयोग करेगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के विविध विकास कार्यक्रमों में वरिष्ठ नागरिकों को कार्यकर्ताओं आंशिक कामगारों के तौर पर शामिल करने के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाएगी।

शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति

विकलांग लोगों का कल्याण और पुर्नवास एक देखभाल करने वाले समाज और एक उत्तरदायी सरकार के हमारे दृष्टिकोण का एक अभिन्न भाग है। भाजपा निम्न बातों के लिए प्रतिबद्ध है–

- विकलांग लोगों के अधिकारों से संबंद्ध विधेयक को कानूनी रूप देना।
- अन्य तौर पर योग्य विद्यार्थियों को घर में ही **ई–लर्निंग** के जरिए कम खर्च में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना यानि विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना।
- देश भर में प्रत्येक एवं विशेष जरूरतमंद व्यक्ति की पहचान करना। इसके लिए एक वेब आधारित **विकलांगता पंजीकरण** प्रणाली शुरु करना और तमाम सरकारी लाभों (स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, रोजगार, शिक्षा आदि) के लिए सार्विक पहचान पत्र (यूनिवर्सल आईडी) जारी करना।
- विकलांगों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करना।
- विकलांग की देखभाल करने वाले पारिवारिक सदस्य के लिए उच्च कर राहत प्रदान करना।

युवा वर्ग– न रुकने वाला भारत

हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम नीतियों की समीक्षा करेंगे और उनमें सुधार करेंगे ताकि युवा निर्णय प्रक्रिया में और राष्ट्र निर्माण लेने वाले निकायों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो।

- हम तमाम क्षेत्रों में युवा नेता कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसका मकसद अतिरिक्त रूप से प्रतिभावान युवाओं की पहचान करना, उन्हें पुरस्कृत करना और उन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल करना है ताकि वे दूसरों के लिए रोल मॉडल और मार्गदर्शक बनें।
- राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद की स्थापना करना।
- नए प्रयोगों, आविष्कारों एवं उद्यमशीलता को प्रौत्साहित करने के लिए भाजपा देश भर में जिला स्तर पर कार्यक्रम चलाएगी।
- विद्यार्थियों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और ऋणों को वहनीय बनाया जाएगा।
- पूरे भारत में पड़ोसी बच्चों/युवाओं की संसद की स्थापना करना ताकि जीवंत विद्यार्थी समितियां बनें।
- विकास के लिए युवा कार्यक्रम की शुरुआत

खेल संवर्धन

भाजपा समाज में और तमाम आयुवर्गों के लिए खेलकूद के महत्व को समझती है।

- भाजपा तमाम खेलों–पारंपरिक एवं आधुनिक का संवर्धन करेगी।
- खेलकूद के लिए ज्यादा धन आवंटित किए जाएंगे।
- स्कूल स्तर पर खेलकूद की संस्कृति पनपाने के लिए कदम उठाए जाएंगे और खेलकूद को स्कूल पाठ्यक्रम का निर्वाय हिस्सा बनाने के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएंगी।
- एक 'राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा खोज प्रणाली' शुरु की जाएगी।
- ऐसे प्रतिभावान लड़कों एवं लड़कियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। मौजूदा ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय महिला खेलकूद महोत्सवों को विस्तृत किया जाएगा ताकि उन्हें हर एक गावं में पहुचांया जाए और प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें विकसित और श्रेष्ठ बनाया जाए।
- देशभर में खेलकूद अकादमियां स्थापित की जाएंगी।
- खिलाड़ियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगीं।

महिलाएं–राष्ट्र निर्माता

भाजपा यह भी मानती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की सुरक्षा एक पूर्व–शर्त है और वह महिलाओं के कल्याण के लिए निम्न कदम उठाएगी–

- सरकार के अंतर्गत तमाम स्तरों पर महिला कल्याण एवं विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भाजपा संविधान संशोधन के जरिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को प्रतिबद्ध है।
- कन्याओं को बचाने एवं उन्हें पढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान–**बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ** छेड़ेगी।
- बालिका समृद्धि, लाडली लक्ष्मी और चिरंजीवी योजना जैसी पहले की सफल योजनाओं की सर्वोत्तम बातों को शामिल करते हुए एक व्यापक योजना तैयार करेगी ताकि कन्याओं के प्रति परिवारों में सकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले।
- **महिलाओं के स्वास्थ्य** की देखभाल के लिए एक मिशन की तरह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें ग्रामीण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के पोषण एवं गर्भाधान पर विशेष जोर रहेगा।
- महिलाओं के लिए समर्पित आईटीआई और अन्य आईटीआई में महिला शाखाओं की स्थापना की जाएगी।
- महिलाओं से संबंधित कानूनों, खास तौर पर बलात्कार से जुड़े कानूनों का कड़ाई से कार्यन्वयन किया जाएगा।
- बलात्कार पीड़ितों की राहत एवं उनके पुर्नवास के लिए धनराशि केन्द्र में बिना उपयोग के पड़ी हुई है क्योंकि यूपीए सरकार ने इसके इस्तेमाल की प्रक्रिया तय नहीं की है। भाजपा प्राथमिकता के आधार पर इस काम को अंजाम देगी।
- एसिड हमले की शिकार महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार एक कोष बनाएगी ताकि ऐसी पीड़ितों के इलाज और कॉस्मेटिक सर्जरी के मेडिकल खर्च को उठाया जाए।
- पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के अनुकूल बनाया जाएगा और विभिन्न स्तरों पर पुलिस में महिलाओं की सख्या बढ़ाई जाएगी।
- महिलाओं की जरूरतों के मद्देनजर अखिल भारतीय महिला चलित बैंक की स्थापना की जाएगी।
- हरेक जिले में महिलाओं के लिए समर्पित लघु एवं मध्यम स्तरीय उपक्रम स्थापित किए जाएंगे।

- आंगनबाड़ी कामगारों की कार्य–परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और उनकी पगार बढ़ाई जाएगी।
- संपत्ति के अधिकारों, वैवाहिक अधिकारों और सहजीवन अधिकारों में किसी भी असमानता को दूर किया जाएगा।
- महिलाओं के लिए विशेष प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम शुरु किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं झुग्गियों की महिलाओं पर विशेष जोर रहेगा।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला स्व–सहायता समूहों को निम्न ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध हो।

शिक्षा– पढ़ो और आगे बढ़ो

भाजपा मानती है कि राष्ट्र की तरक्की के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली औजार है और गरीबी से लड़ने के लिए सबसे ताकतवर हथियार है। शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं की भारी कमी, शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता और अधिकतर कोर्सों से जुड़ी रोजगार परकता की समस्या का समाधान निकालने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा पर सरकारी खर्च को बढ़ाकर जीडीपी का 6 फीसदी किया जाएगा और निजी क्षेत्र को इसमें शामिल कर इसमें और इजाफा किया जाएगा।

सभी के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा के तहत भाजपा निम्न कदम उठाएगी:

स्कूली शिक्षा

- एनडीए का प्रमुख कार्यक्रम **'सर्वशिक्षा अभियान'**।
- माध्यमिक विद्यालय शिक्षा को सार्विक किया जाएगा और प्रयोगात्मक स्कूल के जरिए हुनर विकास को गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें खास तौर पर ग्रामीण, आदिवासी एवं मुश्किल इलाकों पर जोर रहेगा।
- भिन्न रूप से योग्य विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण–पद्यति विकसित की जाएगा।
- मदरसों के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक राष्ट्रीय आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरु किया जाएगा।
- मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन एवं सेवा प्रदान करने के संदर्भ में पुनरुत्थान किया जाएगा।

- स्कूल के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय **ई–पुस्तकालय** की स्थापना की जाएगी।

उच्च एवं पेशेवर शिक्षा

नीतिगत आधार पर निम्न कदम शामिल किए जाएंगे :

- भौतिक एवं मानव–श्रम संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा।
- उद्योग (लघु एवं मध्यम दर्जे के उपक्रम समेत), अकादमिक क्षेत्र एवं समुदाय के बीच करीबी संवाद एवं सम्पर्क के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- उच्च शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विभिन्न कदमों में स्वायत्ता प्रदान की जाएगी।
- नियामक निकायों की विश्वसनीयता बहाल की जाएगी। वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया जाएगा और इसका एकमात्र आधार योग्यता एवं सामर्थ्य होगा।
- यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) का पुनर्गठन किया जाएगा और इसे महज एक अनुदान वितरण एजेंसी के बजाए एक उच्च शिक्षा आयोग का रूप दिया जाएगा।
- कार्य–प्रशिक्षण अधिनियम की इस तरह समीक्षा की जाएगी कि वह हमारे युवाओं को सीखने के दौरान ही कमाई का जरिया प्रदान करें।

रोजगारपरक प्रशिक्षण

- व्यापक स्तर पर खुले ऑनलाइन कोर्सों और वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना की जाएगी ताकि कामकाजी लोगों एवं घरेलू महिलाओं के लिए यह अपना ज्ञान एवं योग्यता बढ़ाने का जरिया बने।
- स्व–रोजगार के नए क्षेत्रों, परिवार संचालित कारोबारों, उद्यमशीलता एवं नए प्रयोगों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम शुरु किए जाएंगे और ये कोर्स महिलाओं के लिए मुक्त होंगे। इसका मकसद उभरते क्षेत्रों में पैदा किए जा रहे रोजगारों के लिए युवाओं को तैयारी करना, नए प्रयोगों एवं सद्यमशलता की भावना को बढ़ावा देना होगा जिससे कि ज्यादा रोजगार पैदा हों एवं आमदनी हो।
- भाजपा शिक्षा पर एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करेगी, जो शिक्षा के हालात एवं आवश्यक सुधारों पर दो वर्षों के अदंर अपनी रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर, भाजपा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा नए प्रयोगों एवं शोध के संदर्भ में जनता की बदलती जरूरतों के अनुरूप एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करेगी।

हुनर–उत्पादकता एवं रोजगारपरकता पर जोर

हमें इस क्षमता पर खरा उतरते हुए दुनिया की सबसे बड़ी **श्रमशक्ति** तैयार करनी है।

हमें भारत को एक **ज्ञान शक्ति** भी बनाना है।
हम हुनर विकास को अभूतपूर्व पैमाने पर एक मिशन की तरह लेंगे।

- हुनर आकलन–भारत की आवश्यकता के अनुरूप अपने राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास की वैज्ञानिक ढंग से योजना बनाना।
- एक **''राष्ट्रीय बहु–हुनर मिशन''** की शुरुआत की जाएगी।
- हम रोजगारपरक हुनरों पर जोर देते हुए शाम में लघु कालिक कोर्स चलाएंगे।
- हम बड़े पैमाने पर रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को बढ़ावा देंगे।
- हम निरन्तर शिक्षा के जरिए योग्यताओं को ताजा एवं प्रोन्नत करने के लिए संस्थागत प्रणालियां भी तैयार करेंगे ताकि उन्हें रोजगार योग्य रखा जा सके।
- **रोजगारपरकता** बढ़ाने के लिए हम सॉफ्ट कौशल प्रदान करने पर ज्यादा जोर देंगे। इसमें विदेशी भाषाओं पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शामिल किया जाएगा।
- लोगों, खासकर युवाओं की कम्प्यूटर साक्षरता के जरिए **डिजिटल सशक्तिकरण** के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाएं–पहुंच बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, लागत को कम करना

भाजपा स्वास्थ क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य देखभाल का व्यापक लक्ष्य राज्य सरकारों की मदद से तमाम भारतीयों को स्वास्थ्य आवस्ति प्रदान करना और सेहत की देखभाल पर जेब खर्च को कम करना है। हमारी सरकार स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में निम्नलिखित सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें साफ तौर पर निर्देश होगा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल मुहैया करायी जाए और यह न केवल आम आदमी की पहुंच के अंदर हो बल्कि प्रभावी हो व वाजिब कीमत पर उपलब्ध हो।
- शिक्षा एवं प्रशिक्षण : स्वास्थ्य देखभाल में लगे विविध पेशेवर नियामक निकायों की भूमिका की समीक्षा की जाएगी और स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक संयोजनकारी निकाय की स्थापना पर विचार करेगी। स्वास्थ्य देखभाल करने वाले पेशेवरों की कमी दूर करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए आधारभूत ढांचे और नवीनतम प्रौद्योगिकियों को समुन्नत किया जाएगा।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पुर्नगठन किया जाएगा। इसका मकसद प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य देखभाल खाद्य एवं पोषण तथा औषधियों से जुड़े विधि विभागों को सम्मिलित करना है।
- मानव संसाधनों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेडिकल एवं पैरा–मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रत्येक राज्य में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- भारतीय औषधि प्रणाली और आधुनिक विज्ञान एवं आयुर्वेदिक–अर्थशास्त्र के लिए एकीकृत पाठ्यक्रमों की शुरुआत करेगें। हम सस्थान स्थापित करेगें और आयुर्वेदिक औषधि के स्तरीयकरण एवं मानकीकरण के लिए एक जोरदार कार्यक्रम चलाएंगें।
- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को स्कूल पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया जाएगा।
- ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने पर जोर रहेगा।
- वरिष्ठ नागरिकों की सेहत की देखभाल करना भी विशेष ध्यान वाला क्षेत्र होगा।
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं–108 को सार्विक किया जाएगा।
- महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पर जोर रहेगा। इस कार्यक्रम को भी बतौर मिशन चलाया जाएगा।
- कुपोषण को खत्म करने के लिए मिशन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा।
- राष्ट्रीय मच्छर नियंत्रण मिशन शुरु किया जाएगा।

खराब साफ–सफाई एवं गदंगी का दूरगामी प्रपाती असर होता है। हम सुनिश्चित करगें कि वर्ष 2019 में गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ तक **''स्वच्छ भारत''** का निर्माण करें। हम इसे एक मुहिम की तरह चलांएगे। इसके लिए तमाम संसाधनों को एकजुट किया जाएगा और जन भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

- खुले में शौच करने से मुक्त भारत का सृजन किया जाएगा। इसके लिए जागरुकता

अभियान चलाया जाएगा और लोगों को अपने घरों तथा स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थानों में शौचालय बनाने में समर्थ किया जाएगा।

- आधुनिक, वैज्ञानिक **सीवेज एवं कचरा प्रबंधन** प्रणालियों की स्थापना की जाएगी। हम अपने शहरों एवं नगरों की साफ–सफाई का आकलन करेंगे और इसके आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करेंगे तथा सबसे बढ़िया कार्य–प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करेंगे।
- सभी को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि पानी–जनित बीमारियां घटें। इससे भारत खुद ही डायरिया–मुक्त हो जएगा।

आर्थिक पुनरुत्थान

हम सरकार में लोगों का विश्वास और विश्वसनीयता वापस लाएंगे, हम देश भर में विश्व स्तर पर भी भारत के आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करेंगे। हम अपनी सतत् दूरगामी नीतियों के बल पर न केवल आर्थिक विकास को गति प्रदान करंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यह विकास स्थिर और संतुलित हो। हम–

- विकास के कार्यों के लिए आवश्यक साधनों से समझौता किए बिना राजस्व के अनुशासन को सख्ती से कार्यान्वित करेंगे, जैसे मनरेगा आदि कार्यक्रम।
- विकास को गति देने वाले सभी उपक्रमों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से संसाधन उपलब्ध कराएंगे।
- विदेशी और देश के निवेशकों के लिए जो नीतियां बनाई गईं हैं, उनका पुर्नमूल्यांकन करेंगे, जो दोनों के लिए सहायक हो।
- बैंकिंग सुधार भी किए जाएंगें।
- हम बचत को बढ़ावा देंगे।

एनपीए

साल दर साल एनपीए की मात्रा बढ़ती जा रही है। पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है। भाजपा ऐसे कदम उठाएगी जिससे बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए में कमी आए। भाजपा एक ऐसा मजबूत नियामक निकाय बनाएंगी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से निवेशकों की रक्षा करेगी

कराधान– कर प्रणाली

भाजपा ने यह महसूस किया है कि कर नीतियों का रोडमैप तैयार होना चाहिए जिससे लोग भविष्य के लिए योजनाएं बना सकें.

- विश्वसनीय, गैर विरोधाभासी और सहायक कर वातावरण तैयार करना।
- कर प्रणाली को तार्किक और आसान बनाना।
- सभी राज्य सरकारों को **जीएसटी** (वस्तु और सेवा कर) के लिए तैयार करना, उनके पूरे पक्ष को सुनते हुए।
- अनुसंधान और विकास के लिए टैक्स लाभ प्रदान करना जिससे तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा मिले।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

मल्टी ब्रांड खुदरा निवेश में विदेशी निवेश का विरोध। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की केवल उन्हीं क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी जहां नौकरी और पूंजी का निर्माण हो। जहां आधारभूत ढांचे के लिए तकनीकी और विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता हो। भाजपा छोटे और मझोले दुकानदारों के हित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है

लघु उद्योगों और उनके कर्मचारियों के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और निवेशकों की सहायक होगी।

कृषि– उत्पादकता, विज्ञान और उसका पारितोषक

कृषि भारत के आर्थिक विकास का इजंन है. सर्वाधिक लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। भाजपा कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता किसानों की आय और ग्रामीण इलाकों के विकास वृद्धि का वादा करती है।

- कृषि और ग्रामीण विकास में सरकारी निवेश बढ़ाया जाएगा।
- ऐसे कदम उठाए जाएंगे, जिससे कृषि क्षेत्र में लाभ बढ़े। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लागत का 50 प्रतिशत लाभ हो। सस्ते कृषि उत्पाद और कर्ज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ज्यादा उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाये जायंगे।
- 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी, जो छोटे और सीमांत किसानों और मजदूरों के लिए होंगी।
- कम पानी से सिंचाई करने वाली तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पानी के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जाएगी, जिसकी अभी तक केवल बात की जा रही है। इससे किसानों को बेहतर आय हो सकेगी और नौकरियों का सृजन होगा। हमारा उद्देश्य **'एग्रो फूड प्रोसेसिंग कल्वर'** की स्थापना करना है, जो बड़े स्तर का हो और जहां निर्यात वाला सामान पैक कर सीधे बाहर भेजा जाए।
- आर्गेनिक फार्मिंग एंड फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया' की स्थापना की जाएगी, जिसमें आर्गेनिक खेती और खाद को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा।
- बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को राहत देने के लिए कृषि बीमा योजना लागू की जाएगी।
- ग्रामीण इलाकों में कर्ज की सीमा बढ़ाई जाएगी।
- बागवानी, फूलों की खेती, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।
- साफ पानी में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, मछुआरों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- कलस्टर संरक्षण गृह का निर्माण किया जाएगा।
- एपीएमसी कानून में सुधार लाया जाएगा।

अनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) खाद्य को बिना वैज्ञानिक जांच पड़ताल के अनुमति नहीं दी जाएगी।

भाजपा **'नेशनल लैंड यूज पालिसी'** स्वीकार करेगी। इसमें गैर कृषि भूमि का वैज्ञानिक तरीके से अधिग्रहण होगा और इसका विकास किया जाएगा। इसमें किसानों के हित का संरक्षण किया जाएगा और इस देश के खाद्य उत्पादन और आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखा जाएगा। नेशनल लैंड यूज अथॉरिटी इसे लागू करने की निगरानी करेगी, जो राज्य की लैंड यूज अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करेगी, जो जमीन के प्रबंधन को नियंत्रित करेगी और सुविधाएं भी देगी। दूसरे नियंत्रक निकाय की तरह नेशनल लैंड यूज अथॉरिटी के पास वही शक्तियां होंगी जो अन्य नियन्त्रक अथॉरिटी के पास होती हैं।

उद्योग– आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और देखभाल करने वाला

हम अब वैश्विक उद्योग के लिए केवल बाजार ही नहीं बनना चाहेंगे। हमें तो वैश्विक उत्पाद केन्द्र बनना है। हमें तो उद्योग को नये–नये तरीके अपनाने व विश्वस्तर पर सहयोग करना है। हमें उद्योग को प्रोत्साहित करना है कि वह कुशल बने और उत्पादन लागत बाजिब हो।

- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक, बेहतर वातावरण बनाएं, जिससे भारत में व्यापार करना आसान हो जाए।

- हम लालफीताशाही को कम करेंगे, प्रक्रिया को आसान बनाएंगे।
- हम राज्य व केंद्र स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम लाएंगे, जहां पर हर तरह की अनुमति मिलेगी।
- हम ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे कि किसी मेगा प्रोडेक्ट को पास करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार समान ऊर्जा से काम करेंगी। दोनों में बेहतर तालमेल होगा।
- पर्यावरणीय मंजूरी के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्द होगा।
- हम विश्वस्तरीय निवेश और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे जो उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक हब होगा।
- एमएसएमई (सूक्ष्म व लघु मध्यम उपक्रम) क्षेत्र की समीक्षा व पुनरोत्थान के लिए एक कार्यबल का गठन करेंगे

विनिर्माण

शक्तिशाली निर्माण क्षेत्र न केवल मांग व आपूर्ति के बीच की खाई को पाटेगा, जिससे कीमतों में स्थिरता आएगी, बल्कि लाखों रोजगारों का निर्माण कर कामगार वर्ग की आमदनी भी बढ़ाएगा। सबसे बढ़कर यह सरकार के राजस्व में वृद्धि करेगा और आयात का विकल्प तैयार कर आयात खर्च को भी कम करेगा। हम भारत को लागत–प्रतियोगी श्रम आधारित और भारी मात्रा में निर्माण करने वाली धुरी बनाएंगे। निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भाजपा–

- ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कदम उठाएगी तथा अनिश्चितता दूर करने और निवेशक के विश्वास की बहाली के लिए स्पष्ट कर नीति लाएगी।
- व्यापार करने को आसान बनाने के लिए सभी कदम उठाएगी, जैसे स्वीकृतियों में आड़े आ रही लाल–फीताशाही को हटाना, साजो–सामान संबंधी आधारभूत ढांचे में निवेश करना, बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा श्रम सुधारों को लागू करना। निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कदम उठाएगी।
- निर्माण क्षेत्र में प्रतियोगी भावना को बढ़ाने के लिए अनुसंधान व विकास पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाएगी तथा शोध व विकास पर उद्योगों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देगी।
- सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर निर्माण इकाइयों की स्थापना को सुगम बनाएगी।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम (एमएसएमई)

भाजपा का मानना है कि हमारे देश के आर्थिक विकास में लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्र की अहम भूमिका है। इस क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र को निर्यात के लिए अंतराष्ट्रीय संपर्क उपलब्ध कराने, समर्पित एमएमई बैंक के जरिये आसान कर्ज दिलाकर, आपूर्ति श्रृंखला की कार्यकुशलता से सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर, शोध व

विकास व नवाचार में सहायता कर तथा बड़ी परियोजनाओं के लिए लघु–मझोले उद्योगों से अनिवार्य खरीद की नीति अपनाकर यह विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। लक्ष्य यह है कि एसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाया जाये जिससे ये हमारी आर्थिक वृद्वि तथा रोजगार सृजन में ज्यादा योगदान दे सके।

सहकारी क्षेत्र

सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर प्रयास किये जाएगें भाजपा वर्तमान में मौजूद सहकारी क्षेत्र से जुड़े कानूनों की समीक्षा करेगी तथा उनमें मौजूद छिद्रों व विसंगतियों को दूर करने के लिए उनमें संशोधन करेगी।

हस्तशिल्प

धातुकर्मियों, बुनकारों, काष्ठकारों, केशसाजों, चर्मकारों तथा कुम्हारों जैसे हस्तशिल्पियों की कार्यकुशलता के उन्नयन और उनके लिए व्यापार अवसर बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।

- राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय व दोनों बाजारों से जोड़ेंगे।
- ऋण, सूचना और कौशल तक सुलभ पहुंच बनायेंगे।

कारीगर

लुहार, बुनकर, बढ़ई, केश–कर्तक, चर्मकार और कुम्हार आदि समुदाय के कौशल विकास व उनके व्यवसाय को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए नयी योजनाएं बनाई जायेंगी।

सेवाएं–गुणवत्ता व कुशलता पर आधारित

व्यवसाय व व्यापार

- त्रुटि विहीन उत्पादों पर ध्यान देना।
- विश्व स्तरीय बंदरगाहों का निर्माण, सड़क व रेल मार्गों द्वारा इन्हें भीतरी भागों से जोड़ना ताकि देश में समुद्री व्यापार को गति मिल सकें।
- देशभर में एयर कार्गो सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।
- निर्यात संवर्द्धन मिशन की स्थापना की जाएगी।
- निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर और आयात पर निर्भरता कम कर चालू खातो में घाटे को कम किया जाएगा। हमारे उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन सबसे बड़ा कार्य होगा।
- हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि समुचित समय सीमा के भीतर जीएसटी जो लाया जा सके। इसे लागू करने के लिए एक मजबूत आईटी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- हम बौद्विक संपदा अधिकारों और पेटेंट के मार्ग पर पूरी तैयारी से चलेंगे।
- खुदरा विक्रेताओं, छोटे व्यापारों और विक्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएगें। उन्हें आधुनिक बनाने तथा उनकी प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों तथा तरीकों से लैस किया जाएगा।
- संस्थागत कर्ज की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगें।
- पुराने व अनगिनत कानूनों की समीक्षा करेगें ताकि उन्हें कम किया जा सके और सरल बना सकें।

पर्यटन–असीम संभावनायें

भाजपा पर्यटन व मेहमानबाजी द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने व हर साल लाखों रोजगार पैदा करने में निभाई जा रही भूमिका को पहचानती है। पर्यटन सामाजिक–आर्थिक प्रगति में प्रमुख भूमिका निभाता है। इससे रोजगार निर्माण होता है, उपक्रम व ढांचागत विकास होता है तथा विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। भाजपा महसूस करती है कि पर्यटन क्षेत्र को विकास के लिए स्पष्ट योजना की जरूरत है भाजपा का वादा है कि 50 पर्यटन सर्किट बनाने के लिए मिशन की तरह परियोजना आरंभ की जाएगी। सभी बजट के अनुकूल ये सर्किट क. पुरातत्व व विरासत, ख. सांस्कृतिक व आध्यात्मिक, ग. हिमालयी, छ. मरूस्थलीय, उ. समुद्रतटीय, च. चिकित्सकीय (आयुर्वेद व आधुनिक) इत्यादि विषयों के गिर्द निर्मित किये जाएंगे। इससे ढांचागत निर्माण होगा, प्रत्येक पर्यटक सर्किट के चारों ओर रोजगार बढ़ेगा तथा राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

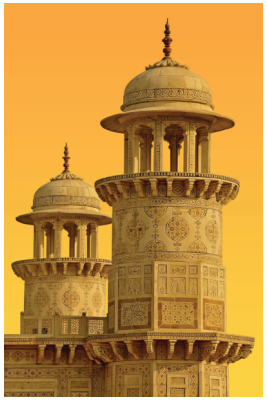

क्षमता विकास के लिए पर्यटन में विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू किए जाएगें पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रम बल – हमारी वृद्वि का स्तंभ

हम सुनिश्चित करेंगे कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के हितों की सुरक्षा हो।

सगंठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हम उद्योग मालिकों व मजदूरों से उद्योग परिवार की अवधारणा को अपनाने का प्रस्ताव करते है।

- श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करना और उनको उच्चकोटी की शिक्षा व स्वास्थ्य प्रदान करना।
- वर्कर बैंक की स्थापना करना।
- पेंशन और स्वास्थ्य बीमा को मजबूत करना।

आवास– अब एक सपना नहीं

हम बड़े पैमाने पर कम मूल्य वाले आवास कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि जब राष्ट्र स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करे तो हर परिवार का स्वयं का एक पक्का मकान हो।

हमारा यह प्रस्तावित कार्यक्रम इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ये घर मूलभूत सुविधाओं से सम्पन्न होंगे। यह सब करने के लिए हम निम्नांकित करेंगे:–

- शहरी क्षेत्रों में भूमि को एक संसाधन के रूप में उपयोग और ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल कार्मिकों की मांग के रूप में उपयोग।
- साथ ही साथ आवासीय क्षेत्र की सभी परियोजनाओं को उपयुक्त नीति निर्धारण, ऋण उपलब्धता और ब्याज योजनाऐं बनाकर प्रोत्साहित करना।

भौतिक आधारभूत ढांचा–सर्वोत्तम से भी बेहतर

- फ्रेट कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कार्य को गति देना। इससे लोगों और वस्तुओं के आवागमन की गति तेज हो जाएगी।
- पूर्वात्तर के राज्य और जम्मू एवं कश्मीर को विश्व स्तर के राजमार्ग, रेलमार्ग द्वारा शेष भारत से जोड़ा जाएगा।
- सीमावर्ती तथा तटीय राजमागों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण प्रकल्पों को गति दी जाएगी।
- सभी गांव अच्छी सड़कों से जोड़े जाएंगे।
- हम मौजूदा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करेंगे, साथ ही छोटे शहरों और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर नये हवाई अड्डों का निर्माण करेंगे।
- हम बंदरगाह नीति विकास का एक आर्थिक मॉडल तैयार करेंगे। भारत को एक लंबा समुंद्री तट वरदान रूप में मिला है। हम इस मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक बनाएंगे, साथ ही नए विकसित करेंगे और ये सब हमारे महत्वाकांक्षी प्रकल्प **'सागर माला'** में एक सूत्र में पिरोए होंगे।
- निजी क्षेत्रों के संसाधनों और उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए एक संस्थागत ढांचा

स्थापित किया जाएगा। इनके विनियामकों को और अधिक स्वायत्ता दी जाएगी, साथ ही इसकी जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी।

भविष्य का आधारभूत ढांचा

- हम परिवारों और उद्योगों को गैस उपलब्ध कराने के लिए गैस ग्रिड की स्थापना करेंगे।
- ग्राम स्तर तक एक **राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क** विकसित करेंगे और सार्वजनिक क्षेत्रों में वाई–फाई क्षेत्र भी अपनी उन्नत और विशेषज्ञ उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग विकास के लिए करेंगे।

परिवहन

भाजपा राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक एकता के लिए यात्रा के महत्व को बखूबी जानती है।

हम –

- एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बनाएंगे, जिससे निजी वाहनों से यात्रा करने का अभ्यास कम हो, इससे यात्रा के समय और लागत में कमी आएगी और प्रदूषण भी कम होगा।
- सड़कमार्ग, रेलमार्ग और जलमार्ग के विभिन्न माध्यमों को समन्वित कर एक सार्वजनिक परिवहन प्रकल्प को प्रारंभ करेंगे।
- यात्रियों और वस्तुओं के परिवहन के लिए जलमार्ग को विकसित करेंगे।
- वस्तुओं के तीव्र आवागमन हेतु **'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नेटवर्क'** विकसित करेंगे।

रेलवे

- भीतरी प्रदेश नए रणनीतिक रेल नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न बंदरगाहों से जोड़े जाएंगे।
- **ऐग्री रेल नेटवर्क** की स्थापना।
- **पर्यटन रेल** जिसमें तीर्थाटन रेल भी सम्मिलित होगी।
- नव्यतम और भव्यतम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रेलवे का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ और कुशल मानव संसाधनों का विकास किया जाएगा।
- यात्रियों की **सुरक्षा** को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही पुराने पड़ गए ढांचे के सुधार में बहुप्रतीक्षित और चेतावनी प्रणाली तथा कठोर मानको में निवेश किया जाएगा।
- **डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट** की स्थापना।

पानी– इसे हर घर को, हर खेत को और कारखानों को उपलब्ध करना होगा

भाजपा जल–संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की पक्षधर है।

- हर खेत को पानी देने के उद्देश्य से **'प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना'** का शुभारंभ करेंगे। किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए हम बहुआयामी जल रणनीति का भी शुभारंभ करेंगे। वर्षों से लंबित सिंचाई प्रकल्पों को शीघ्र पूरा करके सिंचित भूमि को बढ़ाएंगे।
- वर्षाजल संरक्षण, जल संरक्षण और पानी के सदुपयोग को प्रोत्साहित करेंगे।
- नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे।
- तटीय शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए शुद्धिकरण प्लांट लगाएंगे।
- व्यावहारिकता के आधार पर नदियों को आपस में जोड़ेंगे।

सबको पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए हम

- कम पानी वाले क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति वाले ग्रिड बनाने को प्रोत्साहित करेंगे।
- विकेंद्रीकृत, मांग–निर्धारित, सामुदायिक स्तर पर जल संसाधन प्रबंधन, जल आपूर्ति व पर्यावरणीय साफ–सफाई को बढ़ावा दगें।
- घरों में पाईप द्वारा पानी की आपूर्ति सुलभ कराऐंगे।

ऊर्जा : ज्यादा बनाओ, सावधानी से उपयोग करो, बर्बाद बिल्कुल न करो

निर्भरता कम करने और आपूर्तिकर्ता में विविधता को सुनिश्चित करने ताकि एक ही आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता न रहे, और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने के लिए कदम उठाने होंगे। इसके लिए भाजपाः–

- एक जिम्मेदार और व्यापक 'राष्ट्रीय ऊर्जा नीति' बनाएगी।
- ऊर्जा के आधारभूत ढाचें, मानव ससांधन विकास तथा प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के प्रयासों पर फोकस करना।

- तेल, गैस, पनबिजली, सागर, पवन ऊर्जा, कोयला तथा नाभिकीय स्त्रोतों का अधिकतम उपयोग करने के लिए कदम उठाना।
- इस समय बहुत कम उपयोग की जा रही पन बिजली के उत्पादन के लिए छोटे पनबिजली घरों की स्थापना, छोटे प्रोजेक्ट स्थानीय सहयोग से और बिना स्थानीय आबादी को विस्थापित किए लगाए जा सकते है।
- मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए कोयले की खोज को बढ़ाने के कदम उठाना। तले तथा गैस सबंधीं अन्वेषण को भी गति दी जाए। इससे आयात की राशि में कमी आएगी।
- भारत के ऊर्जा स्त्रोतों में एक महत्वपूर्ण अंग अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के उपयोग को भी बल देना।
- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का विस्तार करना और सशक्त करना।

विज्ञान एवं तकनीक : भारत नवाचार करता है तथा भारत नेतृत्व करता है

भारत एक ज्ञानसंपन्न अर्थव्यवस्था रही है और पुरातन काल से ही विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अग्रणी रही है। अब भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी पुनर्स्थापना के लिए नई नीतियां और कार्यक्रमों को बनाने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पहचानी है, ताकि मानवता के आधार पर विज्ञान के माध्यम से आमजन का कल्याण हो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शहरी व ग्रामीण तथा अमीर–गरीब के बीच की खाई को पाटने की कृत क्षमता है। वैज्ञानिक शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी को नई दृष्टि और आभार के साथ प्रोत्साहित करने, प्रचारित करने तथा उपयोग करने की बड़ी आवश्यकता है।

भारतवासियों के जीवनस्तर को उन्नत करने, विशेषकर समाज के वंचित वर्ग को समर्थ करने, भारत को शैक्षिक स्तर पर प्रतियोगी बनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित रूप

में उपयोग करने, पर्यावरण का संरक्षण करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्त्व को भाजपा रेखांकित करती है। हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार हेतु उच्चतम स्तर पर अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र में, घरेलू व विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करेंगे।

हम निम्नांकित बिंदुओं पर विशेष बल देंगेः–

- विज्ञान एव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आमजन के लिए योजना, कृषि, पौष्टिकता एवं पर्यावरणीय सपंदा, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा संरक्षण।
- अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक क्षेत्रों के निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं में आपसी तालमेल बनाकर अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना। कृषि (विशेषकर मृदा, जल–प्रबंधन, मानव तथा पशु पोषण, मत्स्य पालन), जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा, संचार माध्यम तथा परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी, बायो–टेक्नोलौजी तथा अन्य शाखाओं में प्रौद्योगिकी का व्यापक और विशेष उपयोग किया जाएगा।
- जलवायु परिवर्तन तथा मौसम के पूर्वानुमान सबंधीं चुनौतियों, बाढ, तूफान, भूकंप , अकाल तथा भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव तथा इनके शमन हेतु अनुसंधान तथा अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय विकास तथा सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना और अंतराष्ट्रीय संबंधों को सृदृढ़ करने के लिए भी इसका उपयोग करना।
- आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु कार्यक्षमता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना तथा पेशेवर अवसर उपलब्ध कराना ताकि रिसर्च आदि कैरियर अधिक आकर्षक बने और राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ मेधा का उपयोग करके, राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ा सके, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़े और भारतीय मेधा का पलायन रूके।
- नैनो टेक्नोलॉजी, थोरियम टेक्नोलॉजी, मस्तिष्क अनुसंधान व विज्ञान की अन्य शाखाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु विश्व स्तर के केंद्र विकसित करना।
- विभिन्न देशों तथा विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु सहयोग बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र विकसित करना। साथ ही अन्वेषकों की भौतिक संपदा के संरक्षण तथा विस्तार हेतु एक 'भौतिक संपदा अधिकार व्यवस्था' को लागू करना।
- आद्यौगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में तादात्म्य स्थापित करना। विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की इकाई के रूप में स्वायत्त प्रौद्योगिकी रूपातंरण संस्थाओं की स्थापना करके नई तकनीकों को उद्योगों को उपलब्ध कराना। साथ ही औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक नई तकनीकों के संवर्धन के लिए उद्योग जगत को प्रोत्साहित करना कि वे शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थानों को मदद दें और उन्हें अपनाऐं।

- राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को विकसित और प्रचारित करने के प्रयास करना।
- भौतिक संपदा के संवर्द्धन और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए अपनी दीर्घा और समृद्व परंपरानुसार स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण विकास हेतु प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना।
- हिमालयीय प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन हेतु एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।
- दवाइयों, उद्योग तथा कृषि के क्षेत्रों में नाभिकीय विज्ञान के उपयोग और उसके अनुसंधान को बढ़ावा देना।

पेड़ पौधे, जीव जंतु और पर्यावरण – अपने भविष्य को सुरक्षित करना

हम जलवायु परिवर्तन संबंधी शमन कार्यों को पूरी गंभीरता के साथ अंजाम देंगे और वैश्विक समुदाय व संस्थानों के साथ मिल–जुलकर कार्य करेंगे। हम निम्नांकित कदम उठाएंगेः–

- साफ स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- साफ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देंगे ताकि प्रदूषण का स्तर, खासतौर पर शहरों में कम हो सके।
- प्रो–एक्टिव कार्बन क्रेडिट की संकल्पना को बढ़ावा देना।
- वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के इकोलॉजिकल ऑडिट और विभिन्न शहरों और बस्तियों के प्रदूषण सूचकांक का अध्ययन करना।
- प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न उपक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर करना।
- बंजर भूमि का उपयोग सामाजिक वनक्षेत्र के लिए करना।
- वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्द्धन हेतु सुनिश्चित और कारगर कदम उठाना।

पुर्नवनरोपण, कृषि वानिकी और सामाजिक वनक्षेत्रों के विकास हेतु निर्धारित कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।

- कूड़ा–कचरा के निपटान और अवशिष्ट–प्रबंधन हेतु नवाचारोन्मुख प्रक्रियाओं, विशेषकर रीसाइक्लिंग तकनीकों को प्रोत्साहित करना।

हिमालय

- विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों को समन्वित कर अंतर–सरकारी साझेदारी के अंतर्गत एक अद्भुत और अभूतपूर्व कार्यक्रम **''नैशनल मिशन ऑन हिमालय''** प्रारंभ करना।
- हिमालय संरक्षण फंड की स्थापना।
- हिमालय प्रौद्योगिकी को समर्पित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।
  हिमालय के ग्लेशियर जहां से उत्तर भारत की अधिकतम नदियां निकलती है, को पिघलने से रोकने के लिए विशेष कार्यक्रमों को महत्व देकर कार्यान्वित करना।

प्राकृतिक तथा राष्ट्रीय संसाधन–आवश्यकता अनुसार उपयोग, जहां आवश्यक हो वहां संरक्षण

- हम अत्यंत संवेदनशील प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, खनिज, स्पेक्ट्रम आदि के विषय में उपयुक्त और सर्वहितकारी राष्ट्रीय नीतियां बनाएगें। सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखित में होगा कि कौन सा संसाधन किस समय, किस गति से उपयोग करना है, स्थिरता के लिए यह उपयोग किस प्रकार से रणनीतिक रूप से निर्णीत होना चाहिए, इसके दोहन के लिए किसे और क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, और वह भी किस मूल्य पर ।
- इन संसाधनों के दोहन के विषय में राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श किया जाएगा।
- हम अनमाले और महंगे ससांधनों की नीलामी के लिए अनके प्रभावशाली तरीकों, ई–नीलामी सहित, लागू करेंगे।
- ससांधनों के मानचित्रण, खुदाई तथा प्रबंधन में उच्चतम तकनीकी का प्रयोग करेंगे।

भारतीयों की सुरक्षा–आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध बिलकुल सहन नहीं होगा

सपूंर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं के बारे में नहीं बल्कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह सैन्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, भोजन, जल और स्वास्थ्य सुरक्षा, समाजिक सौहार्द और एकजुटता को भी सम्मिलित करती है।

सांप्रदायिक दंगों, माओवादियों के हमलों, पाकिस्तान समाधित आतंकी संगठनों के लगातार बढ़ते हमलों, पूर्वात्तर सीमा से अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय राजधानी में हमलों ने सबको झकझोर दिया है। इस स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए एक स्पष्ट, कठोर और प्रभावी रोडमैप के महत्व को जानती है।

आंतरिक सुरक्षा : भाजपा

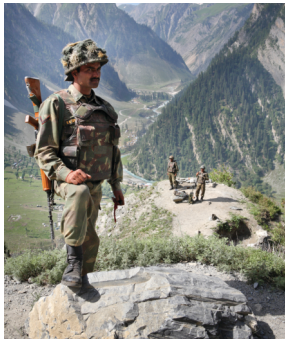

- आतंकवाद प्रतिरोधी तंत्र को पुनर्स्थापित करेगी, जिसे कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका को और सशक्त करेगी और आतंक से संबधित मामलों की निष्पक्ष और त्वरित जांच करेगी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सुधार कर इसे सभी क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु समर्थ करेगी। खुफिया सूचनाओं के न्यूनतम समय में प्रसार की जिम्मेदारी इसकी होगी। डिजिटल व साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- खुफिया एजेंसियों को राजनीतिक दखलंदाजी और हस्तक्षेप से बचाएगी।
- खुफिया जानकारियां एकत्र करने के लिए खुफिया विभाग को आधुनिकतम सुविधाओं से लैस करेगी।
- राज्य सरकारों को अपनी पुलिस फोर्स को आधुनिकतम बनाने और उन्हें पूरी तरह से नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए पूरी सहायता देगी। यह काम सर्वोच्च मिशन के रूप में किया जाएगा।
- नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के तंत्र को मजबूती एवं विस्तार देते हुए एक समूह तैयार किया जायेगा, जो सामाजिक सुरक्षा, आत्मरक्षा और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में उपयोगी होगा।
- माओवादी उग्रवाद के खतरों से निपटने के लिए राज्य सरकारों की सहभागिता से उनसे परामर्श करके एक राष्ट्रीय योजना बनाएगी। उग्रवादियों के गुटों से संवैधानिक ढ़ाचे के अतंर्गत सशर्त बातचीत होगी।
- पूर्वात्तर और अन्य राज्यों के प्रवासी कामगारों और अन्य समुदायों की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस कदम उठाएगी।

बाह्य सुरक्षा : भाजपा

- रक्षा उपकरणों, सहायक सेवाओं, संगठनात्मक सुधारों तथा अन्य संबद्ध मसलों से संबंधित सुधारों की ओर ध्यान देंगे।
- प्राथमिकता के आधार पर रक्षा बलों में कमीशन व गैर–कमीशन अफसरों की बढ़ती कमी को समयबद्ध रूप से दूर करेगी।
- एक रैंक, एक पेंशन योजना को लागू करेगी।

- हमारें सैनिकों की वीरता को मान्यता और सम्मान देने के लिए एक युद्ध स्मारक का निर्माण कराएगी।
- शार्ट सर्विस कमीशन को आकर्षक बनाने के लिए उपाय करेगी।
- राष्ट्रीय नौवहन प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जो सर्वोत्तम ढांचागत संरचना से सुसज्जित होगा तथा तटीय सुरक्षा पर ध्यान देगा।

- सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी, प्रतिरक्षा में शोध व विकास को बढावा देगी जिससे स्वदेशी रक्षा तकनीकों का विकास हो सके तथा रक्षा सबंधी खरीद को गति प्रदान करेगी।
- सीमा पार आतंकवाद से सख्ती के साथ निपटेगी।
- सीमा प्रबंधन की समीक्षा तथा उसमें सुधार करेगी। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए दण्डात्मक उपाय करेगी।
- मानव शक्ति की कमी को दूर करने के लिए समर्पित चार रक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगी।
- पूर्व सैनिकों की तकलीफों की सुनवाई के लिए पूर्व सैनिक आयोग का गठन करेगी। पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) में सुधार तथा पूर्व सैनिकों के पुर्नरोजगार इस आयोग के कार्य क्षेत्र में होंगे।

रक्षा उत्पादन

अपने कुशल मानव संसाधन तथा तकनीकी प्रतिभा के बल पर भारत प्रतिरक्षा हार्डवेयर निर्माण तथा सॉफ्टवेयर उत्पादन में वैश्विक मंच के रूप में उभर सकता है। भाजपा रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (डीआरडीओ) को और मजबूत बनाएगी, कुछ चुने हुए रक्षा उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी समेत निजि क्षेत्र की भागीदारी व निवेश को बढ़ावा देगी। रक्षा निर्माण में तकनीकी हस्तांतरण को अधिकतम स्तर तक प्रोत्साहित किया जाएगा।

स्वतंत्र सामरिक नाभिकीय कार्यक्रम

हम दोधारी स्वतत्रं नाभिकीय कार्यक्रम अपनाएगें जो विदेशी दबाव और प्रभाव से मक्त हो तथा नागरिक व सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता हो क्योंकि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नाभिकीय शक्ति का बड़ा योगदान है।

- इसके लिए भाजपा भारत के नाभिकीय सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करेगी, तथा इसमें संशोधन कर इसे वर्तमान दौर की चुनौतियों में प्रासंगिक बनाने के लिए इसका अध्ययन करेगी।
- भारत के स्वदेशी थोरियम प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में निवेश करेगी।

विदेश संबंध–राष्ट्र प्रथम – वैश्विक बंधुता

पांच 'प'–परंपरा, प्रतिभा, पर्यटन, पण (व्यापार) और प्रौद्योगिकी में हमारी शक्तिओं की सहायता से हम भारत को ब्रांड के रूप में पुनः स्थापित करेंगे।

हमारी विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित रहेंगेः–

- दूर दर्शिता तथा परस्पर लाभदायक व अन्योन्याश्रित संबंधों के सिद्धांत के द्वारा समीकरणों को ठीक किया जाएगा जो स्पष्ट राष्ट्रीय हित पर आधारित है।

- आतकंवाद तथा वैश्विक तापवृद्धि जैसे मुद्दों पर हम एक समान अतंरराष्ट्रीय राय का पक्ष लेंगे।
- बड़ी शक्तियों के हितों द्वारा निर्देशित होने की बजाए हम अपने आस–पड़ोस में तथा इससे परे देशों के साथ एवं विवेक के आधार पर सक्रिय रूप से व्यवहार करेंगे।
- अपने आस–पड़ोस में हम मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देंगे। लेकिन जहां कहीं जरूरी हुआ वहां हम सख्त रूप से कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे।
- हम दक्षेस और आसियान जैसे क्षेत्रीय मंचों को शक्तिशाली बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।
- ब्रिक्स, जी20, आईबीएसए, एससीओ तथा एसएईएम जैसे वैश्विक मंचों के साथ हम संवाद, संलग्नता तथा सहयोग जारी रखेंगे। राज्यों को कूटनीति में बृहत्तर भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अपने पारस्परिक सांस्कृतिक व व्यावसायिक हितों की मजबूती व दोहन के लिए राज्य सक्रिय रूप से विदेशों के साथ संबंध बना सकेंगे।
- विदेशों में बसे अप्रवासी भारतीय तथा मूल के निवासी वहां मौजूद पूंजी की तरह हैं जो राष्ट्रीय हितों व मामलों की विश्वस्तर पर सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर सकता है। भारत ब्रांड को मजबूती देने के लिए इस विशाल जन संसाधन का उपयोग किया जाएगा।

- अपनी जमीन से उजड़े हिंदुओं के लिए भारत सदैव प्राकृतिक गृह रहेगा और यहां आश्रय लेने के लिए उनका स्वागत किया जाएगा।

सांस्कृतिक विरासत

भाजपा का उन मुद्दों पर स्पष्ट रूख है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े हैं।

राम मंदिर : भाजपा अपना रूख दोहराती है। संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाए।

रामसेतु : रामसेतु हमारी सांस्कृतिक विरासत का अंग है और थोरियम भंडारों के कारण इसका सामरिक महत्त्व भी है। सेतु समुद्रम चैनल परियोजना पर निर्णय लेते समय इन तथ्यों पर विचार किया जायेगा।

गंगा : भाजपा प्राथमिकता के आधार पर गंगा की स्वच्छता, शुचिता और अविरल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए वचनवद्व है। इसके अतिरिक्त अन्य नदियों की सफाई के लिए समूचे भारत में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसे नागरिकों के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा।

गाय व गौवंश : खेती में तथा देश के सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में गाय व गौवंश के अमूल्य योगदान को देखते हुए पशुपालन विभाग को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा व सशक्त बनाया जाएगा ताकि गाय व गौवंश का संरक्षण व संवर्द्धन हो सके।

पशुओं की देसी नस्ल में सुधार के लिए कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय पशु विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

विरासत स्थल : सभी राष्ट्रीय विरासत स्थलों के रख–रखाव तथा पुर्नस्थापना के लिए हम समुचित संसाधन उपलब्ध कराएंगे तथा किसी भी रूप में उनके विरूपण व तोड़फोड़ को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अभिलेखागारों, पुरातात्विक व संग्रहालयों के दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। सभी धर्मों व आस्थाओं के तीर्थस्थलों को सुंदर बनाने, उनकी अवसंरचना में सुधार लाने तथा ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा।

भाषाएं : भारतीय भाषाएं हमारे समृद्ध साहित्य, इतिहास, सस्कृति, कला व वैज्ञानिक उपलब्धियों का संग्रहण करती हैं। हमारी अनेक बोलियां हमारी विरासत को जानने की महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। भाजपा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देगी और सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए उपाय करेगी, जिससे कि वे ज्ञान आधारित समाज की रचना के लिए शक्तिशाली माध्यम बन सकें।

समान नागरिक संहिता

भारत के संविधान की धारा 44 में समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई है। भाजपा का मानना है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती है। समान नागरिक संहिता सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने को कटिबद्ध है जिसमें उन परंपराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाएगा।

निष्कर्ष–अमृतमय भारत

हमारा उद्देश्य है आधुनिक, संपन्न और जीवंत भारत– **एक भारत, श्रेष्ठ भारत** की रचना करना जो हमारी नैतिकता और मूल्यों पर आधारित होगा। हमें स्वयं को ज्ञान आधारित समाज व अर्थव्यवस्था में बदलना होगा। जो हमारे विशाल जनबल के अनुभव व ऊर्जा तथा तकनीकी के साधनों से गतिशील होगा। भाजपा इस कार्य के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराती है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनथक रूप से कार्य करने का वादा करती है। इसके लिए हम जनता से साठ महीने मागं रहे हैं।

यह समय थक कर बैठ जाने का नहीं है। यह समय है जब हम सभी को जाग जाना चाहिए और बदलाव लाने के लिए यथाशक्ति अपना योगदान करना चाहिए।

आईये साथ मिलकर **एक भारत, श्रेष्ठ भारत** के निर्माण के लिए भाजपा को वोट करें।

जय हिंद। वंदे मातरम्।